राम प्रसाद राय @राम प्रसाद सिंह

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

23 फरवरी, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और दलवीर भंडारी, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226:

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही-याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई-अपीलकर्ता सी द्वारा एक अन्य रिट याचिका दायर करना/अपीलकर्ताओं को परेशान करने के लिए कथित रूप से शरारत से नामित अन्य व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करना-उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया इस प्रकार अधिग्रहित भूमि पर सड़कों आदि के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश-अपीलकर्ताओं द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई कि भूमि पर सड़क के निर्माण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश, जिसका अधिग्रहण चुनौती के अधीन था और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थाःउच्च न्यायालय को लंबित रिट याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है-विवादित आदेश के संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश उक्त याचिका में किए जाने वाले निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका के निपटारे के बाद लागू होगा।

अपीलार्थियों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उनकी भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।अपीलार्थियों के अनुसार, प्रतिवादी नं।6 ने एक और रिट याचिका दायर की थी, लेकिन वर्तमान अपीलार्थियों को उक्त रिट याचिका में पक्षकारों के रूप में शामिल नहीं किया गया था।उनके द्वारा "जनहित याचिका" के रूप में एक और रिट याचिका दायर की गई थी।अपीलार्थियों ने आरोप लगाया कि याचिका और कुछ नहीं बल्कि उन्हें

परेशान करने के लिए एक शरारतपूर्ण प्रयास था।दाखिल किए जाने के एक दिन बाद इसका निपटारा कर दिया गया। हालांकि, अपीलार्थियों और एक अन्य द्वारा दायर रिट याचिका लंबित थी।इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि भूमि पर सड़क के निर्माण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश दिया गया था, जिसका अधिग्रहण चुनौती के अधीन है।

बिहार राज्य और प्रत्यर्थी सं।6 ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश अपेक्षाकृत हानिरहित है और राम प्रसाद राय 'M प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य [पासायत, जे.] 41 किसी भी तरह से अपीलार्थियों को प्रभावित नहीं करता है।ए.

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को 2004 की लंबित रिट याचिका, सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.3232 का निपटारा करने का निर्देश देना उचित होगा।सड़कों के निर्माण बी के लिए विवादित आदेश में निर्देश उक्त रिट याचिका में निर्णय के आधार पर विचाराधीन रिट याचिका के निपटारे के बाद लागू होगा।[पैरा 10]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2007 की सिविल अपील सं. 911

पटना में सी न्यायिक उच्च न्यायालय के C.W.J.C. सं. 8674/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 3.8.2004 से।

अपीलार्थियों की ओर से एस. चंद्र शेखर और अमित पवन।

उत्तरदाताओं के लिए पी. एस. मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा, तथागट एच. वर्धन, ध्रुव कुमार झा, रवि सी. प्रकाश, मनु शंकर मिश्रा, बी. बी. सिंह, गोपाल सिंह और निशांत डी. पांडे।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था

1.छुट्टी दे दी गई।

2. इस अपील में चुनौती प्रत्यर्थी कुमार सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका में पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

4. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत शुरू की गई कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनकी भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।उक्त रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 6 बम बहादुर सिंह के पिता प्रत्यर्थी संख्या 6 थे।अपीलार्थियों के अनुसार बाम बहादुर सिंह ने उक्त रिट याचिका में उपस्थिति दर्ज कराई थी।एक फुदेना राय ने एक रिट याचिका दायर की जिसे जी को 2004 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2862 के रूप में गिना गया है। उक्त रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ एक प्रार्थना की गई थी कि उसमें उत्तरदाताओं को उस सड़क के निर्माण के लिए आदेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट या रिट, आदेश या आदेश द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है।उक्त रिट याचिका में वर्तमान अपीलार्थी पक्षकार नहीं थे।हालाँकि, वही सुनवाई लगभग उसी दिन हुई जब अपीलार्थियों यानी डब्ल्यू. पी. 3232/2004 द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई हो रही थी।

5. जिस रिट याचिका से वर्तमान अपील संबंधित है, उसे 2004 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 8674 के रूप में गिना गया है और इसे "जनहित याचिका" के रूप में शैलीबद्ध किया गया था।यह अपीलार्थियों का मामला है कि याचिका और कुछ नहीं बल्कि एक शरारतपूर्ण तरीके से बनाई गई थी। बी अपीलार्थियों को परेशान करने का प्रयास।रिट याचिका 2004 के फुदेना राय यानी डब्ल्यू. पी. No.2862 द्वारा दायर रिट याचिका की एक शब्दशः प्रति भी थी।

6. जबकि अपीलार्थियों की रिट याचिका और फुदेना राय की रिट याचिका लंबित थी, विवादित आदेश द्वारा इसे दायर किए जाने के एक दिन बाद निपटाया गया है।क्रम छोटा है और निम्नानुसार पढ़ता हैः

पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की शिकायत है कि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है लेकिन सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता को हाजीपुर में जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली से संपर्क करना चाहिए, जो इस मामले को देखेंगे और देखेंगे कि यदि किसी एजेंसी के तहत धन उपलब्ध है या ग्राम पंचायत अपने स्वयं के कोष से निर्माण करने के लिए तैयार है, तो वह इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।यदि भूमि पर कोई अतिक्रमण होता है, तो हाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली भी उसे हटाने के लिए कदम उठाएंगे। उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।

7. अपीलार्थियों के अनुसार भूमि पर एक सड़क के निर्माण के लिए वस्तुतः एक निर्देश है जिसका अधिग्रहण चुनौती के अधीन है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में 2004 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.2862 को डिवीजन बेंच को भेजा गया और खारिज कर दिया गया।

8. जवाब में, बिहार राज्य के विद्वान वकील और प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रस्तुत किया कि खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश अपेक्षाकृत हानिरहित है और किसी भी तरह से अपीलकर्ताओं को प्रभावित नहीं करता है।

9. यद्यपि आदेश हानिरहित प्रतीत होता है, लेकिन कुछ पहलू हैं जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है।जाहिर है, निर्देश जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली, हाजीपुर या ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण के लिए था।इस बात का कोई संकेत नहीं था कि अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका में निर्णय द्वारा इसे नियंत्रित किया जाना था। यदि उच्च न्यायालय एच ने उल्लेख किया होता कि इन निर्देशों को राम प्रसाद राय @राम प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य [पासायत, जे.] 43 के

निपटारे के बाद निष्पादित किया जाना था, तो अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिका में कोई कठिनाई नहीं होती।

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम महसूस करते हैं कि 2004 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3232 की लंबित रिट याचिका का निपटारा करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश देना उचित होगा। निर्माण के लिए विवादित आदेश में निर्देश उक्त रिट याचिका में निर्णय के आधार पर उपरोक्त रिट याचिका के निपटारे के बाद लागू होगा।

11. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।कोई लागत नहीं।

एसकेएस.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा|